करदाता को फायदा नहीं, वेतन भोगियों को मात्र 25 हजार की छूट

कानपुर (एसएनबी)। सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दीप कुमार मिश्र ने बजट की समीक्षा करते हुए इसमें किये गये निम्नलिखित प्रावधान बताये।

1-व्यक्तिगत कर स्लैब में जो बदलाव किया गए है उनसे करदाता को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है। जब आपकी आय पंद्रह लाख है तो केवल दस हजार रुपये टैक्स का फायदा होगा।

2-वेतनभोगियों को मात्र पच्चीस हजार की अतिरिक्त मानक छूट प्रदान की गयी है।

3-पारिवारिक पेंशन पर मात्र दस हजार की अतिरिक्त मानक छूट प्रदान की गयी है।

4-कानपुर के औद्योगिक जगत से सम्बंधित कच्चे चमड़े पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है।

5-सोना एवं चांदी पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है।

6-लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू की जाएगी जिससे उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे सामान पर ऋण उपलब्ध होगा एवं मुद्रा लोन की रकम दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख कर दी गयी है तथा सिडबी की शाखाएं बढ़ाई जायेंगी।

7-नेशनल पेंशन योजना में कर्मचारी का अधिकतम योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। आप अपने बच्चों के लिए भी इस योजना का लाभ ले सकते है।

8- आगामी छह महीने के अन्दर आयकर कानून की समीक्षा की जायेगी।

9-करदाताओं से विवाद खत्म करने के लिए विवाद से विश्वास तक की नई योजनायें लाई जाएँगी।

10-सर्च एवं सीजर के केस में अब 10 वर्ष की जगह 6 वर्षो का असेसमेंट किया जायेगा।

11-आयकर विभाग अब केवल उन्हीं मामलों में सेकंड अपील करेगा जिसमें कर विवाद की राशि साठ लाख रुपए है। हाईकोर्ट में यह राशि दो करोड़ एवं सुप्रीम कोर्ट में यह राशि पांच करोड़ रुपये होगी।

बजट ने उद्यमियों को किया निराश

दादानगर कोपेस्टेट में बिग स्क्रीन पर हुआ बजट का प्रसारण

कानपुर (एसएनबी)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा केन्द्र सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, उसने उद्यमियों को पूरी तरह निराश किया है। उनका कहना है कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे सन्तोषजनक कहा जा सके।

दादानगर कोआपरेटिव इस्टेट में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने बजट का प्रसारण देखा। इसके लिये इस्टेट सभागार में बिग स्क्रीन लगायी गयी थी। चेयरमैन मलिक विजय कपूर की अध्यक्षता में बजट को देखने के उपरांत एक मीटिंग में सभी ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, मगर इसने तो पूरी तरह निराश किया है। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे सन्तोषजनक कहा जा सके। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा नौकरीपेशा लोगों के लिए यह बजट जरूर राहत देने वाला है। सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बड़े पैकेज दिए, लेकिन उत्तरप्रदेश और खासकर कानपुर में जो उद्यमी बजट से आशा लगाए हुए थे उनके लिये यह बजट पूरी तरीके से निराशाजनक रहा। उद्यमियों के अनुसार सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया जाने का औचित्य समझ में नहीं आया। यहां सुरेश पुरी, हरीश ईसरानी, दिनेश कुशवाहा, बसन्त लाल विश्वकर्मा, आरपी सिंह, विशाल खण्डेलवाल, कार्तिक कपूर, प्रमोद यादव, अखिलेश अग्रवाल, अमित हांडा, नरेश पंजाबी, सुरेश गोयल, सुशील मोहन टकरू, श्याम लाल मूलचंदानी, संजय श्यामदासानी उपस्थित थे।

आयकर के नये प्रावधान अगले छह माह में

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बजट को बताया देश के विकास का रोड मैप

कानपुर (एसएनबी)। अगले 6 माह में आयकर अधिनियम 1961 में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इन बदलावों में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दिए हुए आदेशों को भी शामिल किया जाएगा। इन बदलावों से देश की कर प्रणाली में नई क्रांति आएगी। यह बात इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट आईसीएआई की रीजनल काउंसिल के सदस्य अभिषेक पांडे ने कही। उन्होंने बजट पर बात करते हुए बताया कि सर्च और सर्वे में पहले 10 साल तक के पुराने मामले जिसमें 50 लाख तक से अधिक की कर अपवंचना है, खोले जा सकते थे। लेकिन 2024-25 के बजट से इस प्रावधान में बदलाव करते हुए अब केवल 5 साल तक के पुराने मामले और जिस-जिस वर्ष कार्रवाई हो रही है उस वर्ष के ही सर्च और सर्वे जांच के लिए खोले जा सकते हैं।

इस नियम में बदलाव से करदाताओं के मन में रहने वाली चिंता दूर होगी। वेतनभोगियों को एक छोटा सा लाभ दिया गया है, जिसमें मानक कटौती को थोड़ा बढ़ाया गया है। हालांकि यह उम्मीद के हिसाब से कम है। मानक कटौती को नई रिजीम में 75,000 रुपये किया गया है, जबकि पुरानी स्कीम में अभी भी 50,000 रुपए को बरकरार रखा गया है। वहीं, शहर के चमड़ा कारोबार को थोड़ी राहत दी गई है। इंडस्ट्री में जान डालने के लिए रॉ मैटेरियल में वीसीडी को काम किया गया है। अब इस पर 10 प्रतिशत से कम होकर पांच प्रतिशत ही टैक्स लगेगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स को 5 फीसदी कम किया गया है। अब विदेशी कंपनियों पर 40 प्रतिशत की जगह पर 35 प्रतिशत ही टैक्स लगेगा। इससे विदेशी कंपनियों का देश में निवेश बढ़ेगा। टीडीएस के स्तर पर नया प्रावधान किया गया है कि टीडीएस नहीं जमा करना एक अपराध नहीं है।

सरकार ने बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन को यथा स्थिति 20 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है, जिससे निवेशकों को झटका लगा है। वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन को 15 फीसदी से घटकर 12.5 फीसदी किया गया है, हालांकि इसे और कम किये जाने की उम्मीद थी। इधर, काउंसिल की क्षेत्रीय परिषद के सदस्य अतुल मल्होत्रा ने बजट को विकास उन्मुखी बताया। जैसी उम्मीद थी इस बजट में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पूरे बजट का फोकस युवाओं के रोजगार और कृषि पर दिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लख रुपए किए जाने से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। सीए प्रशांत रस्तोगी ने बताया कि बजट पूरी तरह से उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है।

जीएसवीएम में इंटर्न मेडिकल छात्र हड़ताल पर डटे, गेट पर प्रदर्शन

कानपुर (एसएनबी)। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्र-छात्राएं दूसरे दिन मंगलवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। उन्होंने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन व नारेबाजी की। उन्होंने 'नौकरी नहीं मजबूरी है ये हड़ताल जरूरी है, अबकी बार 30 हजार, एमबीबीएस इंटर्न हैं-बंधुआ मजदूर नहीं' आदि नारे लगाये। हड़ताल के चलते हैलट व सम्बद्ध अस्पतालों की चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो गयीं हैं। मरीजों के इलाज का जिम्मा रेजीडेंट डॉक्टरों पर आ गया है।

वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गये हैं। दूसरे दिन गेट पर हंगामी प्रदर्शन के दौरान इंटर्न छात्रा डॉ. रुचि सिंह ने कहा कि उन्हें प्रति माह 12 हजार मानदेय मिलता है जबकि अन्य प्रदेशों में 25 से 30 हजार रुपये मिल रहे हैं। वर्तमान वेतन मजदूर के वेतन से भी कम है। कई बार प्रयास करने के बाद भी सरकार उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। जब तक तीस हजार वेतन नहीं होगा वह लोग काम नहीं करेंगे। इंटर्न छात्र अभयराज सिंह ने कहा कि एमबीबीएस की पढ़ायी पूरी करने के बाद 12 हजार वेतन मिल रहा है। पूरे प्रदेश में 25 हजार इंटर्न छात्र हैं, जिसमें जीएसवीएम मे 250 इंटर्न छात्र हैं। प्रदर्शन करने वालों में दिव्यांशी मिश्रा, गजेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ नायक, अमिताभ पांडेय, मनीष कुमार गुप्ता, अनुभव राय, आयुष पांडेय, अंश दिवाकर, मोहम्मद रेयान व अन्य शामिल थे। इंटर्न छात्रों के हड़ताल पर जाने से हैलट व अन्य अस्पतालों की इमरजेंसी व इनडोर में भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हो गया है। प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना है कि शासन को हड़ताल के सम्बंध में सूचना भेजी गयी है।

किशोर व युवक ने फांसी लगा दी जान

रावतपुर व गोविंद नगर में हुई घटनाएं

छोटी बहन को रुलाने पर मां ने डांटा, भाई फंदे से झूला

कानपुर (एसएनबी)। रावतपुर में भाई का छोटी बहन के विवाद के बाद गुस्सायी मां ने बेटे को फटकार लगायी तो उसने देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह मां ने जब बेटे का शव दुपट्टे से लटका देखा तो घटना की जानकारी फोन कर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, गोविंद नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर मौत का रास्ता अख्तियार कर लिया।

रावतपुर निवासी मनोज कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिवार में पत्नी सीमा और 11वीं में पढ़ाई करने वाला बेटा अभिनव व एक बेटी सौम्या है। मनोज ने बताया कि सोमवार देर रात दोनों भाई-बहन झगड़ गए। मां ने बेटी को रुलाने से नाराज होकर अभिनव को फटकार लगा दी। देर रात खाना खाने के बाद अभिनव कमरे में गया और उसने माता-पिता व बहन के सोने के बाद फांसी लगा ली। सुबह मां ने अभिनव का शव फंदे से लटका देखा तो घटना की जानकारी फोन कर पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। उधर, गोविंद नगर के संजय नगर निवासी इंदल सिंह फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। घर में पत्नी रेखा और बेटा राहुल सिंह है। बेटा राहुल प्राइवेट नौकरी करता है। देर रात बेटा राहुल खाना खाने के बाद कमरे में चला गया। सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खोला तो राहुल का शव फंदे से लटक रहा था। पिता इंदल ने बताया कि राहुल किसी बात को लेकर तनाव में था और फोन पर किसी से बहस कर रहा था। पुलिस का कहना है कि युवक की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।

आम बजट से कार्पोरेट जगत निराश

कानपुर। आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोल्डी उद्योग समूह के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक **सोम गोयनका** ने कहा कि आम बजट से कार्पोरेट जगत को निराशा हुई है। कार्पोरेट जगत को आशा थी कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इस वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने से भी निराशा ही मिली है। हालांकि सरकार ने गरीब, किसान व मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत दी है। सरकार को रोजगार सृजन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

भारत सरकार के बजट में स्टैण्डर्ड डिडेक्शन में 25000 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुरानी पेंशन व आठवाँ वेतन आयोग पर सरकार ने कोई भी मसौदा पेश न करके केंद्र व राज्य के अधिकारी,कर्मचारी व शिक्षकों को निराश किया है। बजट में बचत में छूट को भी न बढ़ाने से मध्यम वर्ग में समाहित कर्मचारी वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला है। **राजा भरत अवस्थी नगर अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद।**

केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स की सीमा व स्लैब को बढ़ाकर प्रत्येक कर दाता को 17500 रुपये छूट का तोहफा दिया गया है। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एवं 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा जोकि सराहनीय और स्वागत योग्य है। इसी तरह इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से मोबाइल के पार्ट्स और चार्जर सस्ते होंगे, जिससे व्यापारियों व आम जनता को भी राहत मिलेगी। सोने चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी घटाना भी राहत भरा कदम है। शिक्षा लोन में छूट से देश के युवाओं को भी लाभ होगा । **ज्ञानेश मिश्र प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल।**

मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें फूड इंडस्ट्री के लिए कोई भी राहत का पैकेज नहीं दिया गया है। टूरिज्म के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया है और कोई पैकेज नहीं दिया गया है। कुछ समय पूर्व 999 रुपए तक के रूम कर मुक्त थे, वो छूट भी खत्म कर दी गयी है। **श्यामलाल मूलचंदानी, अध्यक्ष कानपुर होटल गेस्ट हाउस एसो. ।**

बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस दौरान निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसानों के लिए कई योजनाएं निकली है। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। ज्यादा पैदावार वाली फसल किस्मों का इस्तेमाल होगा। रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा और स्किलिंग के लिए 1.48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए कलस्टर बनाए जाएंगे। झींगा उत्पादन और रिसर्च पर काम होगा। दालों और तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम होगा। 400 जिलों में फसलों का सर्वे किया जाएगा। 32 फसलों की 109 नई किस्में आएंगी। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र पर बजट में फोकस रहेगा। **डॉ.एसएन सुनील पांडेय, कृषि मौसम विशेषज्ञ।**

बजट सकारात्मक है व सभी वर्गो के लिए विकासोन्मुखी है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निवेशकों की सभी श्रेणियों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने का प्रस्ताव, मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर 20 लाख करना, उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा व समाधान पोर्टल का नवीनीकरण जैसी सुविधाएं स्वागत योग्य है। **नीतू सिंह, उद्यमी।**

न्यू टैक्स रिज्यूम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट अब क्या होगी, 7.75 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को उसके हाथ में कुछ देकर उससे कुछ ले लिया है ऐसा प्रतीत होता है। यह बात जनसाधारण के लिए नहीं है। अभी तक न्यू टैक्स रिज्यूम में 50000 के स्टैंडर्ड डिडेक्शन को मिलाकर इफेक्टिवली 7.5 लाख तक फ्री किया जाता था। वर्ष 2024-25 के स्टैंडर्ड डिडेक्शन की लिमिट को 75000 कर दिया गया है, वहीं टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स लगा दिया गया है। इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया कि सरकार टैक्स में रिबेट देगी या नहीं। **कपिल सब्बरवाल, महानगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल।**

बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है। यह बजट हमारे स्टार्ट-अप्स तथा इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए नए अवसर लेकर आया है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा स्वागत योग्य है। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। **सीए राहुल चंद्रा, सेक्रेटरी कानपुर चार्टेड अकाउंटेंट सोसाइटी।**

केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट सर्वस्पर्शी, सर्वजन के हितों को ध्यान में रखने वाला है। इस बजट में व्यापारियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग के हितों को सपर्श किया गया है। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुद्रा लोन की धनराशि 10 लाख रू से बढ़ाकर 20 लाख रुपये निर्धारित की है, जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दलहन, तिलहन उत्पादन के लिए मिशन मोड में कार्य करने का ऐलान इससे खाने पीने की आवश्यक चीजों की कीमतें नियंत्रित होंगी। टैक्स रिजिम में बदलाव से प्रत्येक कर दाता को कुछ हद तक फायदा होगा। व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम एवं जीएसटी स्लैब में संशोधन की घोषणा यदि होती तो और अधिक लाभ मिलता लेकिन यह एक संतुलित बजट है'। **विनोद गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक, भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र व्यापार प्रकोष्ठ।**

मोदी सरकार के तीसरे बजट में युवाओं को विशेष तौर पर तरजीह दी गई है। रोजगार मुहैया कराने से लेकर स्टार्टअप शुरू करने तक यह बजट युवाओं के विकास का बजट है। आने वाले समय में युवा वर्ग अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करें एवं बिजनेस के क्षेत्र में स्वयं का व्यापार भी शुरू कर सके सरकार ने ऐसी मंशा के अनुरूप इस बजट में युवाओं का ध्यान रखा है'। **विक्रम पंडित, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भाजयुमो।**

'...गया फिर आज का दिन भी निराश करके मुझे' आज के बजट को देखकर एक पुराने गीत की यह लाइन याद आ गई। केन्द्र सरकार द्वारा कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी का दावा करने के बावजूद प्रस्तुत बजट में मोदी सरकार ने एक बार फिर से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लॉलीपॉप देकर निराश किया है। इससे एक बार फिर से मोदी सरकार के मजदूर विरोधी होने के दावे को बल मिलता है। बजट के माध्यम से मोदी सरकार पिछले 10 सालों से मजदूरों की पीठ पर छुरा घोंपने का कार्य कर रही है। **सुशील कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मजदूर कांग्रेस (इंटक)।**

सरकार ने इस बजट में नई जॉब्स क्रिएशन के लिए इंसेंटिव स्कीम और एमएसएमई आदि को सपोर्ट करने के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ायी, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स हटाया, मिडिल क्लास को नई टैक्स नीति के तहत व स्टैण्डर्ड डिडेक्शन बढ़ाने के साथ गोल्ड पर ड्यूटी घटाकर, फिस्कल डेफिसिट का अनुमान कम करके देश को विकसित बनाने के साथ साथ हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। इस बार का बजट इकॉनामी को मजबूत करेगा। एमएसएमई की रुकी ग्रोथ को रफ्तार देने के साथ साथ मध्यम वर्ग को राहत देगा। **पुष्कर विशनोई, सीए।**

प्रस्तुत बजट नगर व ग्रामीण विकास, चिकित्सा, उद्योग, सड़क, ऊर्जा एवं रोजगार के नये अवसर देगा। जिससे विकसित भारत का सपना आकार लेगा और साकार होगा। **डा. शैलेन्द्र दीक्षित,अध्यक्ष श्रमिक बस्ती महासंघ, उप्र**

केंद्र सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह देश की सर्वहारा जनता को शक्ति देने वाला बजट है। इस बजट से मध्य वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। **सुरेश गुप्ता एनडीए नगर संयोजक।**

कानपुर विकास प्राधिकरण — आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुलेखा प्रसाद पत्नी श्री शत्रुघनराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत बैनामा की सत्यापित प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए भूखण्ड संख्या-3/127, ब्लाक-एम0आई0जी0, योजना-स्वर्ण जयन्ती विहार (सतवरी) कानपुर नगर क्षेत्रफल 135.00 वर्गमी0 आवासीय पर नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूखण्ड की फ्रीहोल्ड डीड दिनांक 09.09.2004 को प्राधिकरण द्वारा श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी थी। प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त भूखण्ड के मूल आवंटी श्री सतवीर सिंह की मृत्यु दिनांक 10.02.2011 को हो चुकी है। कार्यालय उपजिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर कार्यालय से निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं0-882/अह0म0फौ0/13 दिनांक 08.03.2013 के अनुसार मृतक स्व0 सतवीर सिंह के निम्नलिखित वारिसान है- 1.श्रीमती मनजीत कौर मृतक की पत्नी उम्र-37 वर्ष 2.कु0 गुरवानी कौर मृतक की पुत्री (अविवा0) उम्र-12 वर्ष 3. प्रभ सिंह मृतक का पुत्र उम्र-08 वर्ष उपरोक्त वारिसानों के अलावा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण में अन्य कोई वारिसान होना नहीं बतलाया गया है। उपरोक्त अंकित वारिसानों के कमांक सं0-1 पर अंकित वारिसान एवं कमांक सं0-2 व 3 पर अंकित वारिसान द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती मनजीत कौर ने उक्त भूखण्ड का विक्रय बैनामा दिनांक 07.10.2013 को श्रीमती सुलेखा प्रसाद पत्नी श्री शत्रुघन राम के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसके आधार पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण श्रीमती सुलेखा प्रसाद पत्नी श्री शत्रुघन राम के पक्ष में किया जाना है। उक्त भूखण्ड पर यदि अन्य कोई वारिसान हो, जोकि अपना हक अधिकार रखता हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्यो सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दें, निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/क्लेम पर विचार न करते हुए नियमानुसार प्रकरण पर नामान्तरण सम्बंधी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन-4)

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: आईआरटीएमटीसी/202425/01 दिनांक : 18.07.2024

भारतीय रेलवे रेल पथ मशीन प्रशिक्षण केन्द्र प्रयागराज

खुली ई-निविदा सूचना

प्रधानाचार्य, भारतीय रेलवे रेलपथ मशीन प्रशिक्षण केन्द्र, पोस्ट- सूबेदारगंज, प्रयागराज, के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई-निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 09.08.2024 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्न प्रकार हैः-

निविदा नं. : IRTMTC-202324-02 | अनुमानित मूल्य (रू.) : 2714489.11

कार्यों का विवरण : कार्य अनुसूची और विशेष परिस्थितियों के अनुसार भारतीय रेलवे रेलपथ मशीन प्रशिक्षण केन्द्र, के बिजली एवं इलेक्ट्रानिक्स संयंत्रों का संचालन, अनुरक्षण एवं मरम्मत।

बयाने की रकम (रू.):54300.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.): 0.00, कार्य समापन की अवधिः 24 माह। नोटः - 1. उपरोक्त सभी ई-निविदाओं का पूर्ण विवरण www.ireps.gov.in पर समय 15:00 बजे टेण्डर बन्द होने की तिथि तक उपलब्ध है । 2. उपरोक्त सभी निविदाओं में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिये कि वे अपने आपको IT Act-2000 के अन्तर्गत CCA द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइनेंसियल रेट पेज पर ही विचारणीय है। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रभार अन्य किसी भी लेटर हेड पर यदि संलग्न है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सीधी तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा। 4. संलग्न किये जाने सभी प्रपत्र निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए । 5. निविदा सूचना को उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in पर मात्र वृहद प्रसार हेतु अपलोड किया जायेगा । 6. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं बयाना राशि की रकम केवल नेट बैंकिंग या पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए । 7. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिये IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाईन से सम्पर्क किया जा सकता है। 8. जी. एस. टी. अधिनियम / कानून/नियम/ दिशा-निर्देश के सम्बंधित प्रावधान लागू होंगे। 1256/24 (AS)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

विशेष रेलगाड़ी का संचालन

भारतीय रेल प्रशासन द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये, निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ी के संचालन का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

गाड़ी सं. 05734/05733 कटिहार जं.-अमृतसर जं.-कटिहार जं. साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी

05734 कटिहार जं.-अमृतसर जं. विशेष गाड़ी			05733 अमृतसर जं.-कटिहार जं. विशेष गाड़ी	
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
---	11:40	कटिहार जं.	15:00	---
06:30	06:40	कानपुर सेन्ट्रल	20:00	20:10
08:15	08:17	इटावा जं.	17:33	17:35
10:33	10:35	अलीगढ़ जं.	15:40	15:42
11:40	11:45	खुर्जा जं.	15:00	15:05
00:10	---	अमृतसर जं.	----	04:25

• कटिहार जं. से : गाड़ी सं. 05734 दिनांक 25.07.24 से 15.08.2024 तक प्रत्येक गुरूवार

• अमृतसर जं. से : गाड़ी सं. 05733 दिनांक 27.07.24 से 17.08.2024 तक प्रत्येक शनिवार

• गाड़ी संरचना : जीएसएलआर/डी-02, सामान्य श्रेणी-04, स्लीपर श्रेणी-14, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-02

नोट : ट्रेन समय-सारणी सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें

उत्तर मध्य रेलवे 1277/24 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड, 89 कैन्ट, कानपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या: 09/अधि0अभि0/न0नि0ख0का0/2024-25, दिनांकः-18.07.2024

महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मोहरबन्द निविदायें उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (यॉत्रिक) में 'ए' श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से दिनांकः-09.08.2024 दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांकः-09.08.2024 को उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपरान्ह 03:00 बजे से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांकः-26.07.2024 से दिनांकः-09.08.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाने पर धनराशि 50.00 रूपये अतिरिक्त देना होगा। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्रेषित करने पर किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी0एस0टी0 (रू0 में) + स्टेशनरी	कार्य की पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	Drilling of 450/550 mm Dia bore by using Rotary rig machine up to 180 Meter depth for construction of 01 no. state tubewell in District- Etawah. Work includes transportation & placement of rig machine and allied equipments at drilling site, digging of pits for storage of water, lowering of recommended MS pipe assembly, maintaining verticality of assembly, welding of all joints properly, screening and feeding of pea gravel after lowering of assembly and washing of bore etc. for proper completion of work including cost of T&P and labor charges etc. MS pipe assembly & POL will be provided by the department free of cost at site as per departmental norms.	180 मी0	02.79 + GST (नियमानुसार)	12000.00	225.00 + GST (नियमानुसार) + 500.00	दो माह
2	Carriage & Supply of Pea gravel size 02.00mm to 03.35mm from Lalkuan quarry, District- Haldwani, Uttarakhand to 01 no. state tubewell in District-Etawah. including loading unloading & stacking at state tubewell site.	43 घन मी0	02.81 + GST (नियमानुसार)			

धरोहर धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर के पदनाम से बन्धक होनी चाहिये। बिना धरोहर धनराशि के तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। विशेष शर्ते/आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ उपलब्ध होगें।

उ.प्र. : 217601 दिनांक : 22.07.2024
वेबसाइट : www.upgov.nic.in

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड, कानपुर

राष्ट्रीय सहारा क्लासीफाइड विज्ञापन

सूचना

मैं अपने पुत्र आदित्य व पुत्रवधू रेनू उर्फ शिवांगी का चाल चलन ठीक न होने के कारण उनसे संबन्ध विच्छेद कर अपने पति की भांति चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया। इनके किसी की भी कृत्य से कोई वास्ता नही। रामकुमारी पत्नी रामकुमार निवासी भैनपुरा कस्बा छिबरामऊ, कन्नौज।

सीबीके-कन्नौज

मैने अपने पुत्र प्रवेश कुमार के गलत चालचलन से तंग आकर संबंधविच्छेद कर अपनी चलअचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उनके कृत्यो से मेरे परिवार का कोई वास्ता नहीं होगा। विशुनचंद्र पुत्र बांकेलाल, निवासी-गौरियापुर पोस्ट मतौली।

सीबीके-कन्नौज

मैं अपने पुत्र गौरव रावत उसकी पत्नी साक्षी वर्मा को उनके गलत-आचरण व व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी चल- अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। इनके द्वारा किये गये कृत्यों से मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमती कृष्णा रावत पत्नी महेश रावत, प्लाट नं.54 मनोहर विहार, बर्रा, कानपुरनगर।

सीबीके-कानपुर

राष्ट्रीय सहारा में वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :- मोबाइलः 8527967695 8115343461, 9935051284

Registration No.: MSCS/CR/803/2013
Regd. Office : 604 A, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110 034
Ph. No. : 011-27355609
Email : info2021kisanagrotech@gmail.com
Website : www.kisanagrotech.in

Notice is hereby given that the Special General Meeting of the Members of M/s. Kisan Agro-tech Cooperative Society Limited will be held on Friday, the 2nd day of August, 2024 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Society situated at 604 A, Pearls Business Park, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110 034 to transact the following business :-
1. Appointment of Statutory Auditors of the Society.
2. Addition of New Members in the Society.
You are requested to make it Convenient to attend the Meeting.

For Kisan Agro-tech Cooperative Society Limited
(Sd./-) Pawan Kumar Kaushik
Vice Chairman
Date : 17.07.2024 Place : New Delhi

Note :
* A member is not entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself.
* Members are requested to immediately intimate any change in their registered address registered with the society.
* All the Statutory Registers can be inspected at the Registered Office of the society during the Business hours i.e. 09:30 to 05:30 PM.

Area of Operations : Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Rajasthan, Punjab and Himachal Pradesh.